



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

राजस्थान

दिसंबर

2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry: +91-87501-87501

Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान	3
➤ राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की प्रगति	3
➤ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नौ नई नीतियाँ लॉन्च की	4
➤ राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जायेंगे	5
➤ राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024	5
➤ जयपुर में आवासीय कॉलोनी में तेंदुआ घुसा	6
➤ राजस्थान में खोजे गए अंधकार युग के सिक्के	8
➤ सरिस्का टाइगर रिजर्व	10
➤ प्रधानमंत्री ने राजस्थान में परियोजनाओं का उद्घाटन किया	11
➤ किसान सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री की कल्याणकारी पहल	13
➤ लिटिल बटिंग पक्षी	14
➤ पवित्र उपवनों के प्रबंधन की नीति	15
➤ मिल्कवीड फाइबर	16
➤ 55वीं GST परिषद बैठक	18
➤ सिरेमिक के लिये उत्कृष्टता केंद्र	19
➤ केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (CGCRI)	20
➤ जयपुर में गैस रिसाव को लेकर NGT ने नोटिस जारी किया	20
➤ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)	21
➤ राजस्थान सरकार ने 9 जिलों को निरस्त किया	21

दृष्टि आईएएम के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

राजस्थान

राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की प्रगति

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के कार्यान्वयन में राजस्थान की प्रगति और चुनौतियों का आकलन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) और राजस्थान:
 - ◆ इसे वर्ष 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।
 - इस मिशन को एक राष्ट्रव्यापी अभियान/जनआंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था।
 - ◆ राजस्थान ने SBM-G पहल के तहत उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है:
 - ODF (खुले में शौच मुक्त) प्लस मॉडल उपलब्धियों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर 10 वाँ स्थान प्राप्त किया।
 - राज्य के 98 प्रतिशत गाँव ODF + घोषित हो चुके हैं।
 - 85% गाँवों ने सफलतापूर्वक ODF + मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है।
- उपलब्धियाँ:
 - ◆ मल कीचड़ प्रबंधन (FSM):
 - वर्तमान स्थिति: केवल 114 ब्लॉकों ने FSM सत्यापन पूरा कर लिया है।
 - ◆ अभी तक कोई ग्रामीण मल-कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP) का निर्माण नहीं किया गया है।
 - ◆ अनुशांसाएँ: शहरी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें।
 - ◆ एक मजबूत FSM नीति को अंतिम रूप देना और लागू करना।
 - ◆ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM):
 - प्रगति: 94% गाँव SWM पहल के अंतर्गत आ गए हैं।
 - सिफारिशें: स्थिरता बढ़ाने के लिये खाद बाजारों को जोड़ते समय पृथक्करण शेड और वाहनों का उचित संचालन सुनिश्चित करना।
 - ◆ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ (PWMU):
 - ग्रामीण राजस्थान में केवल एक कार्यशील PWMU मौजूद है, जिसे महत्त्वपूर्ण पैमाने पर विस्तारित करने की आवश्यकता है।
- ग्रे जल प्रबंधन (GWM):
 - ◆ प्रगति: 98% गाँवों में GWM प्रणालियाँ स्थापित हो चुकी हैं, तथा शेष गाँवों में भी शीघ्र ही पूर्णतः स्थापित हो जाने की आशा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ फोकस क्षेत्र: **जल जीवन मिशन (JJM)** के तहत नल के जल कनेक्शन के लिये घरेलू सेप्टिक टैंक को बढ़ावा देना।
 - स्वच्छता पहल को आगे बढ़ाने में **स्वयं सहायता समूहों** की भूमिका को मजबूत करना।

● पर्यटन और स्वच्छता:

- ◆ राजस्थान से आग्रह किया गया कि वह अपनी समृद्ध पर्यटन विरासत को स्वच्छता पहलों के साथ जोड़े तथा **स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग कार्यक्रम** को अपनाए, ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि परंपरा और नवाचार मिलकर स्थायी स्वच्छता के लिये एकजुट हो सकते हैं।

स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) कार्यक्रम

- यह आतिथ्य क्षेत्र में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिये एक सरकारी पहल है।
- SGLR कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से **जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार** करना है:
 - ◆ होटलों, रिसॉर्ट्स और होमस्टे में विश्व स्तरीय सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करना
 - ◆ पर्यटन स्थलों की प्रतिष्ठा में सुधार।
 - ◆ ODF + मॉडल का दर्जा प्राप्त करने के लिये स्थानीय ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करना।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नौ नई नीतियाँ लॉन्च की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निवेश को बढ़ावा देने और राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से नौ नई नीतियों को लॉन्च किया।

- ये नीतियाँ 9 से 11 दिसंबर 2024 तक जयपुर में आयोजित होने वाले **राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024** से पहले लॉन्च की गईं।

प्रमुख बिंदु

- राज्य विकास पर लक्षित नीतियाँ:
 - ◆ नव अनुमोदित नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य राजस्थान में **आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित** करना है।
 - ◆ राजस्थान के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिये हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन नीतियों को मंजूरी दी गई।
 - ◆ नीतियाँ क्षेत्र-विशिष्ट पहलों पर केंद्रित हैं:
 - **MSME नीति:** इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाना है।
 - **निर्यात प्रोत्साहन नीति:** राजस्थान के उत्पादों की वैश्विक पहुँच बढ़ाने पर केंद्रित।
 - **एक ज़िला-एक उत्पाद नीति:** यह स्थानीय उत्पादकों के लिये बुनियादी ढाँचे का निर्माण करके ज़िला-विशिष्ट शिल्प को समर्थन प्रदान करती है।
 - **पर्यटन नीति:** रोजगार सृजन के लिये **पारिस्थितिकी पर्यटन** और **विरासत पर्यटन** को बढ़ावा दिया जाएगा।
 - **स्वच्छ ऊर्जा नीति:** **सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं** के माध्यम से राजस्थान को **नवीकरणीय ऊर्जा** में अग्रणी के रूप में स्थापित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लनिंग
ऐप



- **खनिज नीति:** वर्ष 2046 तक 1 करोड़ नौकरियों और 1 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **क्लस्टर विकास योजना:** कच्चे माल और प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुँच के साथ क्लस्टर आधारित लघु उद्योग विकास को प्रोत्साहित करती है।

राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जायेंगे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान में नौ नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अवसरों में वृद्धि होगी।

मुख्य बिंदु

- नये स्कूलों के लिये अनुमोदन:
 - ◆ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी।
 - ◆ ये स्कूल 82,000 से अधिक छात्रों को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे।
 - ◆ राजस्थान में नव स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय जोधपुर, गंगानगर, करौली, नागौर, राजसमंद और दौसा जिले में हैं।
 - ◆ इस कदम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना, शैक्षिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और युवा पीढ़ी के समग्र विकास में योगदान देना है।
- व्यापक निहितार्थ:
 - ◆ यह पहल देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में सुधार लाने के सरकार के मिशन के अनुरूप है।
 - ◆ यह भारत के युवाओं के विकास और सशक्तीकरण का समर्थन करता है, तथा राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देता है।

राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर (JECC) में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, 2024 और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024:
 - ◆ निवेश शिखर सम्मेलन का विषय “पूर्ण, जिम्मेदार, तैयार (Replete, Responsible, Ready)” है, जिसमें सतत खनन, जल सुरक्षा और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप पर चर्चा की जाएगी।
 - ◆ 32 से अधिक देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषयगत सत्रों और प्रदर्शनियों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्थान की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा।
- राजस्थान की विकास संभावनाएँ:
 - ◆ राजस्थान में महत्वपूर्ण खनिज भंडार, विशाल प्राकृतिक संसाधन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो इसे एक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ राजस्थान को दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं से लाभ मिल रहा है, जिससे औद्योगिक लॉजिस्टिक्स में सुधार हो रहा है।
- ◆ रणथंभौर और जयपुर जैसे अद्वितीय आकर्षणों के साथ, राजस्थान वन्यजीव, विरासत और साहसिक पर्यटन का केंद्र है।
- नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण में भूमिका:
 - ◆ राजस्थान बड़े सौर पार्कों के साथ भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दे रहा है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य को पूरा करेगा।
 - ◆ मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के तहत, राजस्थान ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में क्षमता निर्माण कर रहा है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME):
 - ◆ राजस्थान MSME क्षेत्र में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है, जहाँ 27 लाख से अधिक इकाइयाँ 50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं।
 - ◆ नई MSME नीतियों और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना जैसी ऋण योजनाओं ने वर्ष 2014 से MSME के लिये ऋण प्रवाह को दोगुना कर दिया है।
 - ◆ राजस्थान में MSME वैश्विक आपूर्ति शृंखला को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)

- ECLGS को कोविड-19 संकट के उत्तर में केंद्र के आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में 2020 में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करना था।
- राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (MLI)- बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को 100% गारंटी प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत जिस ऋण उत्पाद के लिये गारंटी प्रदान की जाएगी, उसका नाम 'गारंटीकृत आपातकालीन ऋण लाइन (GECL)' होगा।

जयपुर में आवासीय कॉलोनी में तेंदुआ घुसा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विद्याधर नगर इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब एक तेंदुआ एक रिहायशी कॉलोनी में घुस आया और उसने तीन लोगों पर हमला कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम ने जंगली बिल्ली को बेहोश कर उसे बचा लिया।

मुख्य बिंदु

- तेंदुआ:
 - ◆ इसका वैज्ञानिक नाम पेंथेरा पार्डस है।
 - ◆ तेंदुआ पेंथेरा वंश की बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटा है, जैसे बाघ, शेर, जगुआर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ। यह विभिन्न प्रकार के आवासों में अनुकूलन करने की अपनी क्षमता के लिये जाना जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





- ◆ तेंदुआ एक रात्रिचर प्राणी है, जो रात में शिकार करता है।
- ◆ यह अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजातियों जैसे चीतल, हॉग डियर और जंगली सूअर को खाता है।
- ◆ तेंदुओं में मेलानिज्म एक सामान्य घटना है, जिसमें पशु की पूरी त्वचा काले रंग की होती है, जिसमें धब्बे भी शामिल हैं।
 - मेलानिस्टिक तेंदुए को अक्सर **ब्लैक पैंथर** कहा जाता है और गलती से इसे एक अलग प्रजाति मान लिया जाता है।
- प्राकृतिक वास:
 - ◆ यह उप-सहारा अफ्रीका, पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे भागों, भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया तक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है।
 - ◆ भारतीय **तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस फ्यूस्का)** एक तेंदुआ है जो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से वितरित है।
- भारत में जनसंख्या:
 - ◆ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट '**भारत में तेंदुओं की स्थिति, 2018**' के अनुसार, वर्ष 2014 के अनुमान से भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है।
 - ◆ वर्ष 2014 के अनुमान के अनुसार तेंदुओं की जनसंख्या लगभग 8,000 थी जो बढ़कर 12,852 हो गयी है।
 - ◆ अनुमान है कि तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश (3,421) में है, उसके बाद कर्नाटक (1,783) और महाराष्ट्र (1,690) का स्थान है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- **खतरा:**
 - ◆ खाल और शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिये अवैध शिकार
 - ◆ आवास की हानि और विखंडन
 - ◆ मानव-तेंदुआ संघर्ष
 - **संरक्षण की स्थिति:**
 - ◆ **IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित
 - ◆ **CITES:** परिशिष्ट-I
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I

राजस्थान में खोजे गए अंधकार युग के सिक्के

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों से 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के पंच-मार्क सिक्कों का खजाना मिला है।

- यह भारतीय इतिहास के “अंधकार युग (Dark Age)” के संबंध में जानकारी प्रदान करता है जो **सिंधु घाटी सभ्यता** के पतन से लेकर **भगवान बुद्ध** के युग तक फैला हुआ है। इतिहासकार 1900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के इस काल को **अंधकार युग** कहते हैं।

मुख्य बिंदु

- **परिचय:**
 - ◆ राजस्थान की पुरातात्विक खोजें इस क्षेत्र की प्राचीन व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती हैं।
 - ◆ ये निष्कर्ष भारत के लुप्त ऐतिहासिक काल को उजागर करने के लिये इन कलाकृतियों के संरक्षण और अध्ययन के महत्व को रेखांकित करते हैं।
- **राष्ट्रीय मुद्राशास्त्र सम्मेलन में प्रस्तुति:**
 - ◆ राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान विभाग के एक सेवानिवृत्त मुद्राशास्त्री ने 5 दिसंबर, 2024 को मेरठ में **राष्ट्रीय मुद्राशास्त्र सम्मेलन** में पंच-मार्क सिक्कों पर अपना शोध प्रस्तुत किया।
 - संग्रहालय विज्ञान संग्रहालयों और उनमें की जाने वाली गतिविधियों का अध्ययन है।
 - इसमें संग्रहालयों के इतिहास, समाज में उनकी भूमिका और उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, जैसे संरक्षण, शिक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का अध्ययन शामिल है।
 - मुद्राशास्त्री वह व्यक्ति होता है जो मुद्रा और धन के रूप में प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं का अध्ययन, संग्रह और विश्लेषण करता है।
 - ◆ उन्होंने अहार (उदयपुर), कालीबंगा (हनुमानगढ़), विराटनगर (जयपुर), और जानकीपुरा (टोंक) जैसी साइटों की खोजों पर प्रकाश डाला, जिसमें एक संपन्न प्राचीन व्यापार नेटवर्क के साक्ष्य प्रदर्शित किये गए।
- **खोजें और महत्व:**
- **व्यापक सिक्का अध्ययन:**
 - ◆ सिक्कों पर सूर्य, षड्चक्र और पर्वत/मेरु जैसे प्रतीक अंकित थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ चाँदी और ताँबे से बने इन सिक्कों का मानक वजन 3.3 ग्राम है तथा ये सिक्के पेशावर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में पाए जाने वाले सिक्कों से समानता दर्शाते हैं।
- प्रमुख निष्कर्ष:
 - ◆ उल्लेखनीय खोजों में 1935 में टोंक में मिले 3,300 सिक्के और 1998 में सीकर में मिले 2,400 सिक्के शामिल हैं।
 - ◆ इन क्षेत्रों के धातुकर्म उपकरण महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पेशावर में पाए जाने वाले औजारों से मिलते जुलते हैं, जो राजस्थान को एक व्यापक सांस्कृतिक और व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ते हैं।
- ऐतिहासिक संदर्भ और पुरातात्विक साक्ष्य:
- चीनी यात्रियों द्वारा दस्तावेज़ीकरण:
 - ◆ चीनी यात्री फा-हियान (399-414 ई.), सुनयान (518 ई.) और ह्वेन-त्सांग (629 ई.) ने इन क्षेत्रों में खंडहरों का दस्तावेज़ीकरण किया, जो उनके ऐतिहासिक महत्त्व की ओर संकेत करते हैं।
 - ◆ उनके विवरण, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ मिलकर, राजस्थान की प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक विरासत की समझ को समृद्ध करते हैं।
- व्यापक व्यापार संबंध:
 - ◆ राजस्थान का व्यापार इतिहास **सिल्क रूट** के समान ही महत्वपूर्ण है, जिसका समर्थन गुप्त वंश, मालव और जनपदों के सिक्कों की खोज से होता है।
 - ◆ ये निष्कर्ष प्राचीन भारत में राजस्थान की महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिका पर जोर देते हैं।
- खजाना संग्रह:
 - ◆ राजस्थान पुरातत्व विभाग ने राजस्थान खजाना नियम, 1961 के तहत संग्रहित 2.21 लाख से अधिक प्राचीन सिक्के एकत्र किये हैं, जिनमें 7,180 पंच-मार्क नमूने भी शामिल हैं।
 - ◆ ये सिक्के राज्य की ऐतिहासिक और आर्थिक प्रमुखता के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।

सिंधु घाटी सभ्यता

- परिचय:
 - ◆ भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के जन्म से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
 - ◆ यह लगभग 2,500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी क्षेत्र, वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुआ।
 - ◆ सिंधु घाटी मित्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता का घर थी।
 - ◆ 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें दो पुराने शहरों, **मोहनजोदड़ो और हड़प्पा** के खंडहरों का पता चला।
 - ◆ 1924 में, **ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल** ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की।
- पतन:
 - ◆ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ई.पू. हुआ, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और प्रवास था।
 - ◆ इसके दो प्रमुख शहर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा लुप्त हो गये, जिससे सभ्यता का अंत हो गया।
 - ◆ हड़प्पा को अक्सर इस सभ्यता के नाम के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि यह आधुनिक पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया पहला शहर था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सरिस्का टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने **सरिस्का टाइगर रिज़र्व के वन्यजीवों** की सुरक्षा और पांडुपोल हनुमान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

मुख्य बिंदु

- **वाहन यातायात पर चिंताएँ:**
 - ◆ न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त कि अनियंत्रित वाहन यातायात से रिज़र्व में वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, विशेष रूप से उन दिनों में जब वहाँ अधिक भीड़ होती है।
 - ◆ यह सुझाव दिया गया है कि वन्यजीवों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने तथा आगंतुकों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये **वैकल्पिक तौर पर इलेक्ट्रिक शटल बसें** शुरू की जाएँ।
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने पारिस्थितिक संरक्षण और धार्मिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये स्थानीय प्राधिकारियों और **केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)** की एक समिति का गठन किया।
- न्यायालय ने मंदिर ट्रस्ट और श्रद्धालुओं की निजी वाहनों के अचानक बंद होने संबंधी चिंता को भी स्वीकार किया, जिससे प्रमुख धार्मिक दिनों में हजारों श्रद्धालु प्रभावित होंगे।

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

- **परिचय:**
 - ◆ सरिस्का टाइगर रिज़र्व **अरावली पहाड़ियों** में स्थित है और राजस्थान के अलवर ज़िले का एक हिस्सा है।
 - ◆ इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा बाद में 1978 में इसे **बाघ अभयारण्य (टाइगर रिज़र्व)** घोषित कर दिया गया, जिससे यह भारत की **प्रोजेक्ट टाइगर** का हिस्सा बन गया।
 - ◆ इसमें खंडहर मंदिर, किले, मंडप और एक महल शामिल हैं।
 - **कंकवाड़ी किला** रिज़र्व के केंद्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि **मुगल बादशाह औरंगज़ेब** ने राजगद्दी के उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने भाई दारा शिकोह को इसी किले में कैद किया था।
 - इसमें पांडवों से संबंधित **पांडुपोल** में **भगवान हनुमान का** प्रसिद्ध मंदिर भी है।
- **वनस्पति और जीव:**
 - ◆ इसकी विशेषता **चट्टानी परिदृश्य, शुष्क झाड़ी-कांटेदार वन, घास के मैदान, चट्टानों और अर्द्ध-पर्णपाती वन** हैं।
 - ◆ इसमें **ढोक, सालार, कडाया, गोल, बेर, बरगद, गुगल, बाँस, कैर** आदि के वृक्षों का प्रभुत्व है।
 - ◆ यह **अन्य विविध प्रकार के पशुओं** जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, सांभर, चीतल, नीलगाय, चार सींग वाले मृग, जंगली सूअर, लकड़बग्घा और जंगली बिल्लियों को भी आश्रय देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रधानमंत्री ने राजस्थान में परियोजनाओं का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 46,300 करोड़ रूपए से अधिक लागत की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

- परियोजनाएँ ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल संसाधनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हैं।

मुख्य बिंदु

पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना:

- यह एक अंतर-राज्यीय नदी जोड़ो पहल है, जिसे मध्य प्रदेश में चंबल नदी से पार्वती, नेवज और कालीसिंध नदियों के अधिशेष जल को राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) तक ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस एकीकरण का उद्देश्य संबंधित राज्यों के बीच जल बंटवारे, लागत-लाभ वितरण और जल विनिमय जैसे मुद्दों का समाधान करना है।
- इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के 21 जिलों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है।
- इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में विकास को बढ़ावा मिलने की आशा है।

परियोजना में शामिल नदियाँ:

चंबल नदी:

- उद्गम: सिंगार चोरी चोटी, विन्ध्य पर्वत, इंदौर, मध्य प्रदेश।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: बनास, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती।

पार्वती नदी:

- उद्गम: विन्ध्य रेंज, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश।
- महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ: कोई नहीं।

कालीसिंध नदी:

- उद्गम स्थल: बागली, देवास जिला, मध्य प्रदेश।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: परवन, नेवज, आहू।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP):

- राज्य सरकार ने जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये ERCP को मंजूरी प्रदान की और उसका विस्तार किया।
- पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के राज्य बजट में महत्वाकांक्षी पेयजल एवं सिंचाई जल परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की घोषणा की गई थी।
 - इन जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर शामिल थे।
- ERCP का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों जैसे चंबल और उसकी सहायक नदियों, जैसे कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध, में वर्ष के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का संचयन करना तथा इस जल का उपयोग राज्य के दक्षिण-पूर्वी जिलों में करना है, जहाँ पीने और सिंचाई के लिये जल की कमी है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

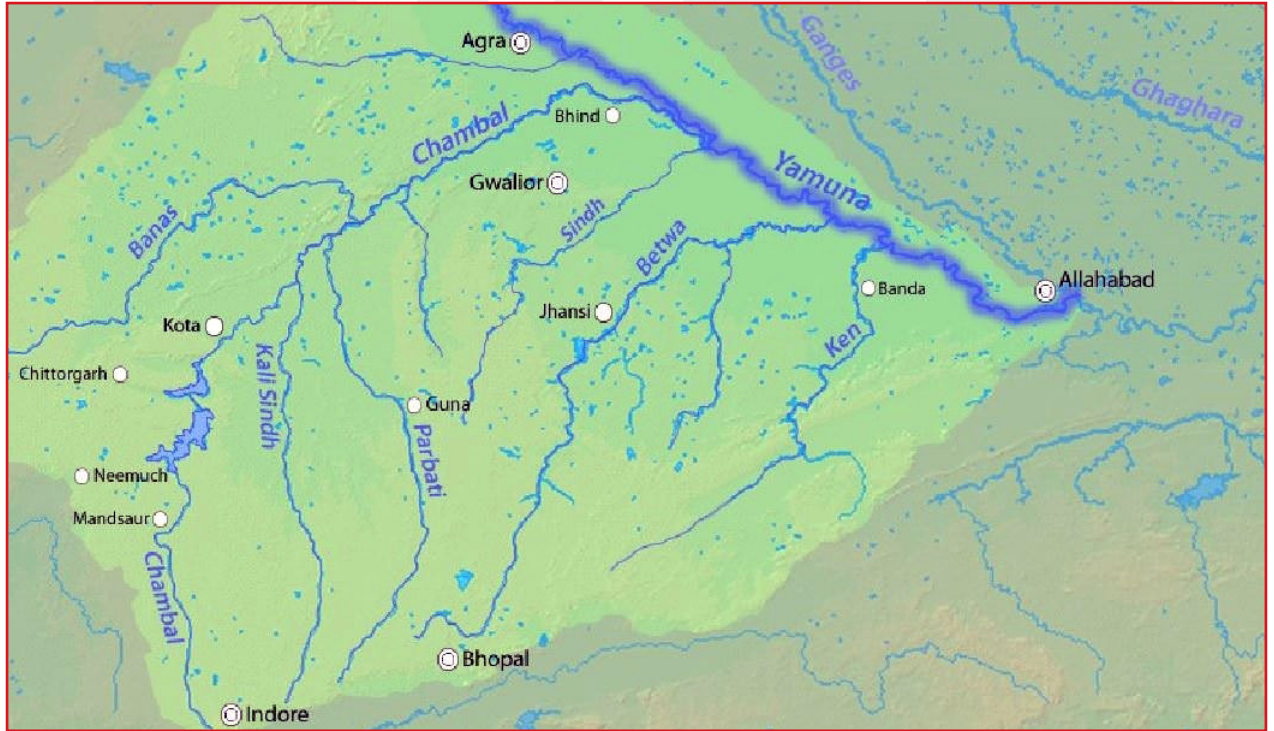


- ERCP की योजना वर्ष 2051 तक दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मनुष्यों और **पशुपालन** के लिये पेयजल और औद्योगिक जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाई गई है।

चंबल नदी

परिचय:

- ◆ यह **विंध्य पर्वत** (इंदौर, मध्य प्रदेश) की उत्तरी ढलानों में **सिंगार चौरी चोटी** से निकलती है। वहाँ से यह मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है और फिर राजस्थान से होकर 225 किलोमीटर की लंबाई तक उत्तर-पूर्व दिशा में बहती है।
- यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा जिले में **यमुना नदी** में मिलने से पहले लगभग 32 किमी. तक बहती है।
- यह एक मानसूनी नदी है, जिसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। चंबल और इसकी सहायक नदियाँ उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को जल प्रदान करती हैं।
- राजस्थान में **हाड़ौती पठार** मेवाड़ मैदान के दक्षिण-पूर्व में चंबल नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।
- सहायक नदियाँ: बनास, काली सिंध, सिप्रा, पारबती, आदि।
- मुख्य विद्युत परियोजनाएँ/बाँध: **गांधी सागर बाँध**, **राणा प्रताप सागर बाँध**, जवाहर सागर बाँध और **कोटा बैराज**।
- राष्ट्रीय **चंबल अभयारण्य** राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, रेड क्राउन रूफड टर्टल (कछुए) और लुप्तप्राय **गंगा नदी डॉल्फिन** के लिये जाना जाता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

किसान सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री की कल्याणकारी पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने **किसान सम्मान निधि** की दूसरी किस्त के रूप में 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये तथा 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध की सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए जमा किये।

मुख्य बिंदु

- **किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:**
 - ◆ **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** के अंतर्गत **ड्रिप एवं सिप्रिंकलर सिंचाई उपकरणों** के लिये 15,983 किसानों को 29 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गए।
 - बाड़ लगाने, पाइपलाइन बिछाने, खेत तालाब निर्माण, जैविक खाद और कृषि उपकरण जैसी गतिविधियों के लिये 14,200 किसानों को 96 करोड़ रुपए वितरित किये गए।
 - **8,000 सौर पंपों** की स्थापना के लिये 80 करोड़ रुपए आवंटित।
- **प्रगतिशील किसानों को मान्यता:**
 - ◆ मुख्यमंत्री ने केंद्र प्रायोजित **ATMA योजना** के तहत 10 नवोन्मेषी किसानों को सम्मानित किया।
- **कृषि में निवेश:**
 - ◆ जयपुर में आयोजित **राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट** के दौरान कृषि में 58,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिये 2,500 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।
- **किसान कल्याण हेतु प्रमुख निर्णय:**
 - ◆ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण।
 - ◆ आठ लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये।
 - ◆ 26,000 सौर संयंत्रों की स्थापना।
 - ◆ 31 स्थानों पर फूड पार्कों के लिये भूमि का आवंटन।
 - ◆ **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर गेहूँ, मूँग, मूँगफली और सरसों की खरीद।
- **नई योजनाओं का शुभारंभ:**
 - ◆ **पशुधन बीमा योजना** शुरू की गई।
 - ◆ **ऊँट संरक्षण** एवं विकास मिशन की घोषणा की गई।
 - ◆ 100 गौशालाओं में **गोबर जलाने वाली मशीनें लगाने का** कार्य आरंभ किया गया।
 - ◆ 1,000 नये दूध संग्रहण केंद्रों का शुभारंभ किया गया तथा 200 नये बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये गये।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

- **परिचय:**
 - ◆ इसे भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- **वित्तीय लाभ:**
 - ◆ देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से हर चार महीने में तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाती है।
- **योजना का दायरा:**
 - ◆ यह योजना शुरू में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिये थी, लेकिन योजना का दायरा बढ़ाकर सभी भूमिधारक किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया।
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन:**
 - ◆ यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
 - ◆ इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न इनपुट प्राप्त करने में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
 - ◆ उन्हें ऐसे व्यय को पूरा करने के लिये साहूकारों के चंगुल में फँसने से बचना तथा कृषि गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।

लिटिल बंटिंग पक्षी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पक्षी प्रेमियों ने **माउंट आबू** में एक छोटा-सा पक्षी देखा, जो राजस्थान में इसकी पहली उपस्थिति थी।

मुख्य बिंदु

- **लिटिल बंटिंग का विवरण और निवास स्थान:**
- **के बारे में:**
 - ◆ लिटिल बंटिंग एक छोटा गौरैया पक्षी है जो बंटिंग और गौरैया परिवार से संबंधित है।
 - ◆ इसका प्रजनन क्षेत्र सुदूर पूर्वोत्तर यूरोप और उत्तरी एशिया के **टैगा** तक विस्तारित है।
 - ◆ यह पक्षी शीतकाल के दौरान दक्षिणी चीन और पूर्वोत्तर भारत की ओर प्रवास करता है तथा आमतौर पर कृषि क्षेत्रों में रहता है तथा अनाज खाता है।
- **विशेषताएँ:**
 - ◆ यह एक छोटा सा ध्वज है, जिसकी लंबाई केवल 12-14 सेमी (4.7-5.5 इंच) होती है।
 - ◆ इसका निचला भाग सफेद होता है तथा छाती और पार्श्व भाग पर काली धारियाँ होती हैं।
 - ◆ अपने भूरे चेहरे और सफेद माला धारी के साथ, यह एक छोटी मादा रीड बंटिंग जैसा दिखता है, लेकिन इसमें काले मुकुट की धारियाँ, एक सफेद आंख की अंगूठी और इसके भूरे गालों के पीछे एक महीन काले रंग की सीमा होती है।
 - ◆ **IUCN रेड लिस्ट:** सबसे कम चिंता
- **जलवायु परिवर्तन की संभावित भूमिका:**
 - ◆ विशेषज्ञों का कहना है कि **जलवायु परिवर्तन** के कारण यह पक्षी राजस्थान की ओर आकर्षित हुआ है, क्योंकि यह अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों से बचता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मांड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





- उत्तरी भारत में दृश्य:
 - ◆ हाल ही में गुरुग्राम, चंडीगढ़ और उत्तरी पंजाब जैसे क्षेत्रों में छोटे-छोटे बंटिंग्स देखे गए हैं।
 - ◆ ये पक्षी आमतौर पर उत्तरी भारत, दक्षिणी चीन और उत्तरी दक्षिण पूर्व एशिया के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं।
 - संरक्षण के लिये महत्त्व:
 - ◆ यह दृश्य इस बात पर जोर देता है कि ऐसी प्रवासी प्रजातियों के लिये वन क्षेत्रों और आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है।

पवित्र उपवनों के प्रबंधन की नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह देशभर में पवित्र उपवनों (Sacred Groves) के प्रबंधन के लिये एक समग्र नीति तैयार करे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा:
 - ◆ केंद्र सरकार से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के माध्यम से पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिये प्रयासों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया।
 - ◆ वन्यजीव और पर्यावास प्रबंधन की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर रही है, फिर भी न्यायालय ने पवित्र उपवनों के संरक्षण के महत्त्व को सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकारों के संदर्भ में रेखांकित किया है।
- पवित्र उपवनों के लिये कार्य योजना:
 - ◆ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पवित्र उपवनों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के लिये एक योजना विकसित करने का कार्य निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें उनके क्षेत्र और विस्तार की पहचान करना भी शामिल था।
 - ◆ केंद्र सरकार को निर्वनीकरण (वनों की कटाई) या भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण पवित्र उपवनों की संख्या में कमी को रोकने के लिये सख्त निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया।
 - ◆ बागों की सीमाओं को चिह्नित किया जाना चाहिये, लेकिन भविष्य में विकास के लिये उन्हें अनुकूलित रखा जाना चाहिये।
- राजस्थान के लिये न्यायालय के निर्देश:
 - ◆ न्यायालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह जमीनी और उपग्रह दोनों तरीकों से पवित्र उपवनों का मानचित्रण करे।
 - ◆ इन उपवनों को वन के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये तथा इनके आकार की परवाह किए बिना इन्हें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- पारंपरिक समुदायों का सशक्तीकरण:
 - ◆ न्यायालय ने पारंपरिक समुदायों को, विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, पवित्र उपवनों के संरक्षक के रूप में सशक्त बनाने का सुझाव दिया।
 - ◆ इन समुदायों को उनके संरक्षण की विरासत को संरक्षित करने और सतत् संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये हानिकारक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

पवित्र उपवन

- पवित्र उपवन वे वन क्षेत्र हैं जो पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदायों द्वारा उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व के कारण संरक्षित हैं।
- ये उपवन स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- पवित्र उपवन सामान्यतः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं।

मिल्कवीड फाइबर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने दूधिया रेशे सहित नए प्राकृतिक रेशों में अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ाकर भारत के कपड़ा उद्योग के विकास में सहयोग को दृढ़ किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- **रणनीतिक सहभागिता:**
 - ◆ भारत के वस्त्र क्षेत्र को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, वस्त्र मंत्री ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित एक बैठक में यूनिक्लो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की।
 - ◆ यह भारत में कपास उत्पादन क्षमता, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी केंद्रित है।
 - ◆ भारत के वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र में यूनिक्लो (Uniqlo) का योगदान:
 - ◆ यूनिक्लो पूरे भारत में 15 स्टोर संचालित करता है, जिससे 31 मार्च, 2024 तक 30% की वृद्धि दर के साथ 814 करोड़ रुपए का खुदरा राजस्व प्राप्त होगा।
- **भारत के वस्त्र विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण:**
 - ◆ भारत ने 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कपड़ा बाजार तथा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है।
 - ◆ मंत्रालय ने यूनिक्लो को प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) पार्कों में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया है, जो सतत् संचालन के साथ एक तैयार पारिस्थितिकी तंत्र की पेशकश करेगा।
- **आगामी सहयोग के अवसर:**
 - ◆ यूनिक्लो फरवरी 2025 में "भारत टेक्स" ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो में भाग लेगा, जिसमें नवाचार, स्थिरता और ट्रेसबिलिटी पर प्रकाश डाला जाएगा।
- **दूधिया रेशा:**
- **परिचय:**
 - ◆ यह दूधिया पौधों से प्राप्त बीज फाइबर है।
 - ◆ मिल्कवीड (एस्क्लेपियस सिरिएका एल) पौधा एस्क्लेपियाडेसी परिवार के एस्क्लेपियस वंश से संबंधित है और इसे जिद्दी खरपतवार के रूप में भी जाना जाता है।
 - ◆ भारत में यह जंगली पौधे के रूप में राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है।
 - ◆ मिल्कवीड की पत्तियों, तनों और फलियों में प्रचुर मात्रा में दूध का रस होता है।
- **गुण:**
 - ◆ इसमें तैलीय पदार्थ और लिग्निन (एक लकड़ी जैसा पौधा पदार्थ) होता है, जो इसे कटाई के लिये बहुत भंगुर बना देता है।
 - ◆ फाइबर की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक मोम के कारण इसकी सतह हाइड्रोफोबिक-ओलियोफोबिक होती है।
- **अनुप्रयोग:**
 - ◆ इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है।
 - ◆ इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग इन्सुलेंटिंग भराव सामग्री के रूप में भी किया जाता है।
 - ◆ इसका उपयोग जीवन रक्षक जैकेट और बेल्ट जैसे जल-सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है।
 - ◆ शोधकर्ताओं ने पाया कि यह आसानी से तेल को सोख लेता है और साथ ही पानी को भी दूर रखता है, इस प्रकार यह तेल रिसाव को साफ करने में सहायता करने वाला एक प्रभावी फाइबर बन जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पीएम मित्र योजना

- पीएम मित्र (PM MITRA) पार्क का विकास एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा तथा यह सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में होगा।
- प्रत्येक मित्रा पार्क में एक इनक्यूबेशन सेंटर, सामान्य प्रसंस्करण गृह, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र तथा अन्य वस्त्र संबंधी सुविधाएँ जैसे डिजाइन केंद्र और परीक्षण केंद्र होंगे।

55वीं GST परिषद बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक आयोजित की गई।

मुख्य बिंदु

- गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।
- GST परिषद की अनुशंसाएँ:
- प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन (EV): GST परिषद ने गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह सभी प्रयुक्त EV की बिक्री पर कर की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है।
- ◆ GST केवल व्यावसायिक बिक्री के मामले में मार्जिन मूल्य (खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, यदि दावा किया गया हो तो मूल्यहास के लिये समायोजित) पर लागू होगा। व्यक्तिगत-से-व्यक्तिगत बिक्री पर कोई GST लागू नहीं होता है।
- बैंकों के दंडात्मक शुल्क: ऋण अवधि के उल्लंघन के लिये बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई GST लागू नहीं होता है।
- भुगतान एग्रीगेटर: 2,000 रुपए से कम के भुगतान को संभालने वाले भुगतान एग्रीगेटर छूट के लिये पात्र होंगे।
- ◆ यह छूट भुगतान गेटवे या फंड निपटान से असंबंधित अन्य फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होती है।
- विमानन टरबाइन ईंधन (ATF): GST परिषद ATF GST के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुई क्योंकि राज्यों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।
- ◆ राज्य ATF को कच्चे पेट्रोलियम डीजल की टोकरी का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि इसे अकेले नहीं हटाया जा सकता।
- ◆ पाँच उत्पादों यानी कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, ATF और प्राकृतिक गैस को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है और राज्य VAT लगाते हैं।
- GST छूट: किसानों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश को GST से छूट दी जाएगी।
- ◆ जीन थ्रेपी को GST से पूरी तरह छूट दी गई है तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर एकीकृत GST छूट को बढ़ा दिया गया है।
- क्षतिपूर्ति उपकर: व्यापारिक निर्यातकों को आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर की दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया।
- यह उपकर GST के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाली किसी भी राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिये चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लनिंग
ऐप



- **पॉपकॉर्न:** GST परिषद ने स्पष्ट किया (कोई नया कर नहीं लगाया गया) कि कैरामलाइज़्ड पॉपकॉर्न पर 18% GST लगाया गया है। नमक और मसालों के साथ रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा, अगर वह पहले से पैक और लेबल वाला न हो और अगर वह पहले से पैक और लेबल वाला हो, तो 12% GST लगेगा।
- ◆ कैरामलाइज़्ड पॉपकॉर्न को शुगर कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 18% GST लगता है, जबकि नमकीन पॉपकॉर्न एक नमकीन है और इस पर 5% GST लगता है।

GST परिषद

- **GST परिषद:** GST परिषद, अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016) के तहत एक संवैधानिक निकाय, GST कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करता है।
- GST एक मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम) और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- **सदस्य:** परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।
- **निर्णयों की प्रकृति:** मोहित मिनरल्स मामले, 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि GST परिषद की अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद और राज्यों के पास GST पर एक साथ विधायी शक्तियाँ हैं।

सिरेमिक के लिये उत्कृष्टता केंद्र

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान में सिरेमिक के लिये एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण और विश्व स्तरीय अनुसंधान के साथ उद्योग को बढ़ावा देने के लिये तैयार है।

मुख्य बिंदु

- **प्रचुर मात्रा में सिरेमिक खनिज भंडार:**
 - ◆ राजस्थान में बॉल क्ले, सिलिकोसिस सैंड, क्वार्ट्ज, चाइना क्ले और फेल्डस्पार जैसे सिरेमिक खनिजों के विशाल भंडार हैं।
 - ◆ राजस्थान में सिरेमिक आधारित उद्योगों और रोज़गार सृजन की पर्याप्त संभावनाएँ होने के बावजूद, प्रसंस्करण के लिये कच्चा माल अन्य राज्यों को भेजा जा रहा है।
- **केंद्र की भूमिका:**
 - ◆ यह केंद्र स्थानीय संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम बनाते हुए सिरेमिक खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिये तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
 - ◆ परिचालन के पहले दिन से ही उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये इसकी सेवाएँ पूर्व-परिभाषित की जाएँगी।
- **फोकस क्षेत्र:**
 - ◆ निम्नलिखित के उत्पादन के लिये सिलिकोसिस खनिजों की खोज पर मुख्य जोर दिया जाएगा:
 - विद्युत आपूर्ति के लिये इन्सुलेटर
 - सेनेटरीवेयर उत्पाद
 - रियल एस्टेट क्षेत्र के लिये टाइलें

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- मिट्टी के बर्तन और ईटें
- इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये **अर्द्धचालक**
- **हितधारक योगदान:**
 - ◆ केंद्र के उद्देश्यों और परिचालन ढाँचे को परिष्कृत करने के लिये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (CGCRI) और **IIT (BHU)** के अधिकारियों सहित प्रमुख विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त हुए।

केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (CGCRI)

- CGCRI एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, जो **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)** के अधीन कार्य करता है।
- 1950 में स्थापित यह संस्थान काँच, चीनी मिट्टी, अभ्रक और रिफ्रैक्टरीज जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञता रखता है।

जयपुर में गैस रिसाव को लेकर NGT ने नोटिस जारी किया

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को जयपुर में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद कई छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में उत्तर देने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

- **घटना:**
 - ◆ NGT ने जयपुर में संदिग्ध गैस रिसाव की घटना पर **स्वतः संज्ञान** लिया।
 - 15 दिसंबर, 2024 को महेश नगर इलाके में घटी इस घटना में एक कोचिंग संस्थान के 10 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जब वे पास के नाले से रिसाव के कारण बेहोश हो गए थे।
- **न्यायाधिकरण की टिप्पणियाँ:**
 - ◆ न्यायाधिकरण ने कहा कि रिपोर्ट में पीड़ितों के लिये किसी मुआवजे का उल्लेख नहीं किया गया था।
 - ◆ पीठ ने **सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991** और **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986** के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।
 - ◆ **प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर** उन्हें अपना उत्तर या प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
 - ◆ न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित पक्षों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया:
 - ◆ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव
 - ◆ जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट
 - **केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** का क्षेत्रीय कार्यालय
 - **जलवायु परिवर्तन**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।
- CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ एवं कार्य भी निर्दिष्ट किये गए।
- यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

राजस्थान सरकार ने 9 ज़िलों को निरस्त किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2023 तक बनाए जाने वाले नौ ज़िलों और तीन संभागों को निरस्त कर दिया है।

मुख्य बिंदु

- ज़िलों और प्रभागों का पुनर्गठन:
 - ◆ राजस्थान में अब 41 ज़िले और सात संभाग होंगे।
 - ◆ पाली, सीकर और बांसवाड़ा संभागों को निरस्त कर दिया गया है।
 - ◆ आठ ज़िलों को “प्रशासनिक आवश्यकताओं” के चलते बनाए रखा गया है।
- निरस्त किये गये ज़िले:
 - ◆ दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर।
- बरकरार रखे गए ज़िले:
 - ◆ बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलोदी और सलुंबर।
- नये ज़िलों से संबंधित प्रशासनिक मुद्दे:
 - ◆ बुनियादी ढाँचे का अभाव:
 - ◆ एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, नए ज़िलों में कार्यालय भवन, प्रशासनिक बुनियादी ढाँचे और आधिकारिक पदों का अभाव था।
 - ◆ 18 विभागीय पदों का सृजन बोज़िल सिद्ध हुआ।
- समिति की अनुशंसाएँ:
 - ◆ एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में नए ज़िलों को अव्यवहारिक पाते हुए उन्हें समाप्त करने की अनुशंसा की गई।
 - ◆ इन ज़िलों की स्थिति की समीक्षा के लिये एक कैबिनेट उप-समिति भी गठित की गई।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

